

एमएसएमई सेक्टर में विकास में मुद्रा बैंक की भूमिका

डॉ. नमता दुबे

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत 8 अप्रैल 2015 को स्थापित मुद्रा (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कोलेटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार तथा जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला।

लॉन्च के दशक (2015-2025) में योजना ने 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए, जिनकी कुल राशि ₹32.61 लाख करोड़ है। महिलाएं कुल लाभार्थियों में 68% हैं, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमी 50% खातों के लाभार्थी हैं। औसत ऋण आकार FY16 में ₹38,000 से बढ़कर FY25 में ₹1.02 लाख हो गया। एमएसएमई क्षेत्र में बैंक ऋण FY14 के ₹8.51 लाख करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹27.25 लाख करोड़ हो गया और FY25 में ₹30 लाख करोड़ पार करने की उम्मीद है।

यह शोध द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, PIB, मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट तथा नीति आयोग की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण शामिल है। निष्कर्ष में पाया गया कि मुद्रा बैंक ने एमएसएमई को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत योगदान दिया है, हालांकि NPA प्रबंधन तथा जागरूकता विस्तार जैसे क्षेत्रों में और सुधार की जरूरत है।

कीवर्ड्स

मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), एमएसएमई सेक्टर, वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, शिशु-
किशोर-तरुण ऋण, महिलाओं का सशक्तिकरण, जमीनी रोजगार सृजन।